



## EDITOR'S SCATVIEW

*Manoj Kumar Madhavan*

*TRAI is getting its act together and trying to set right some of the prevailing anomalies in the broadcast and telecom sector. Recently demonstrated by its action on issuing a consultation paper which deals with the issue of regulating converged digital technologies with a specific focus on enabling convergence of carriage of broadcasting and telecommunication services.*

*Technological convergence brings with it peculiar issues of policy, regulation, data privacy, and data security, hence it is important that policy and regulations evolve on a continuous basis to keep pace with the developments.*

*The paper is notable as it examines challenges posed by converging technologies and explores changes needed in legal, administrative, and licensing frameworks to deal with them, as per TRAI. The proposal is important because it can cause significant disruption to internet businesses.*

*Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has asked the Indian telecom regulator to focus on developing a single regulatory system instead.*

*The other welcome step is in the case of FM broadcasting.*

*Last May, the ministry of information and broadcasting had sought recommendations of the authority, on issues including removal of the linkage to non-refundable one-time entry fee (NOTEF) in the formula for annual fee as prescribed in the FM Ph-III Policy Guidelines of 2011. It had also requested the authority for recommendations on extension of the existing FM license period of 15 years by three years.*

*TRAI had held a meeting with representatives of Association of Radio Operators for India (AROI) last August. Representatives of AROI, had then raised issues such as permitting private FM Radio channels to broadcast independent news bulletins and availability of FM radio receivers in mobile handsets.*

*The National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) granted interim relief to Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) on February 24 and stayed the order directing the initiation of insolvency proceedings against the media and entertainment firm.*

*The appellate tribunal further issued notice to IndusInd Bank on plea by Zee managing director Punit Goenka and said it will hear the case again on March 29.*

*The development comes at a time when ZEEL is at advanced stages of merging with Culver Max Entertainment (Sony) in one of the biggest deals in the media and entertainment sector. It remains to be seen if the merger of Zee – Sony gets delayed due to this development.*

*The All India Digital Cable Federation (AIDCF) and broadcasters have finally reached an agreement over the New Tariff Order (NTO) 3.0, with the cable operators agreeing to sign the fresh Reference Interconnection Offer (RIO). The case in the Kerala High Court will, however continue. The agreement has come after AIDCF members, who moved the court to challenge NTO 3.0, failed to get an interim relief.*

*(Manoj Kumar Madhavan)*

*ट्राई एकसाथ मिलकर काम कर रहा है और प्रसारण व दूरसंचार क्षेत्र में प्रचलित कुछ विसंगतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस बात का प्रदर्शन उसने हालही में जारी एक परामर्शपत्र की सहायता से की, जिसमें प्रसारण और दूरसंचार सेवाओं के कन्वर्जंस को सक्षम करने पर विशेष ध्यान देने के साथ कन्वर्जंस डिजिटल तकनीकियों को विनियमित करने के मुद्दे शामिल हैं।*

*तकनीकी कन्वर्जंस अपने साथ नीति, विनियमन, डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के अजीबोगरीब मुद्दे लाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि विकास के साथ तालमेल रखने के लिए नीति और विनियम निरंतर आधार पर विकसित हों।*

*यह परामर्श पत्र उल्लेखनीय है क्योंकि यह ट्राई के अनुसार तकनीकियों को परिवर्तित करने से उत्पन्न चुनौतियों की जांच करता है और उनसे निपटने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और लाइसेंसिंग ढांचे में आवश्यक परिवर्तनों की पड़ताल करता है। प्रस्ताव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंटरनेट व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर सकता है।*

*सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) जिसने भारतीय दूरसंचार नियामक को इसके बजाय एकल नियामक प्रणाली को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है।*

*अन्य स्वागत योग्य कदम एफएम प्रसारण के मामले में है।*

*पिछले मई में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2011 के दिशानिर्देश के तहत एफएम के तीसरे चरण की नीति में निर्धारित वार्षिक शुल्क फॉर्मूले में गैर-वापसी योग्य एक बार प्रवेश शुल्क (एनओटीईएफ) से लिंकेज को हटाने सहित मुद्दों पर प्राधिकरण की सिफारिशें मांगी थीं। इसने प्राधिकरण से 15 साल की मौजूदा एफएम लाइसेंस अवधि को तीन साल तक बढ़ाने की सिफारिशों के लिए भी अनुरोध किया था।*

*ट्राई ने पिछले अगस्त में एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स फॉर इंडिया (एआरओआई) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। एआरओआई के प्रतिनिधियों ने तब निजी एफएम रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार बुलेटिन प्रसारित करने और मोबाइल हैंडसेट में एफएम रेडियो रिसीवर की उपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाया था।*

*नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) को 24 फरवरी को अंतरिम राहत प्रदान की और मीडिया व एंटरटेनमेंट कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी। अपीलीय न्यायाधिकरण ने जी के प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका की याचिका पर इंडसइंड बैंक को नोटिस जारी किया और कहा कि 29 मार्च को वह मामले की फिर सुनवाई करेगा।*

*यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक में जेडईईएल ने कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (सोनी) के साथ विलय के काफी निकट पहुंच चुका है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या इस विकास के कारण जी-सोनी के विलय में देरी होती है।*

*ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और प्रसारक आखिरकार नये टैरिफ आदेश (एनटीओ) 3.0 पर एक समझौते पर पहुंच गये हैं, केबल ऑपरेटर भी नये रेफ्रेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) ऑफर पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गये हैं। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय में दायर मामला चलता रहेगा। एनटीओ 3.0 को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख करने वाले एआईडीसीएफ के सदस्यों को अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद यह समझौता हुआ है।*

*(Manoj Kumar Madhavan)*